

साप्ताहिक करंट अफेयर्स 19-23 जुलाई 2021

Important News: State

महाराष्ट्र ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य होगा चर्चा में क्यों?

- महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा।
- भारत ब्लॉकचेन-संचालित शैक्षिक दस्तावेजों को शुरू करने वाला सिंगापुर, माल्टा और बहरीन के बाद चौथा देश बन गया।

प्रमुख बिंदु

- महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री ने बताया कि इस तकनीक का इस्तेमाल कर दस लाख डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।
- यह तकनीक LegitDoc द्वारा प्रदान की जाएगी।

LegitDoc के बारे में:

- LegitDoc, बंगलौर स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी क्रॉसफोर्ज सॉल्यूशंस का प्रमुख उत्पाद है जो ब्लॉकचेन DApp विकास में विशेषज्ञता रखता है।
- LegitDoc टैम्पर-प्रूफ डिजिटल दस्तावेज जारी करने और सत्यापित करने के लिए एक एथेरियम-आधारित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है।

ब्लॉकचेन के बारे में:

- ब्लॉकचेन एक तरह से जानकारी रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली है जिससे सिस्टम को बदलना, हैक करना या धोखा देना मुश्किल या असंभव हो जाता है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

गुजरात उच्च न्यायालय अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने के लिए देश का पहला उच्च न्यायालय बना चर्चा में क्यों?

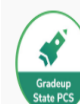
- गुजरात उच्च न्यायालय अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग (सीधा प्रसारण) शुरू करने के लिए देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया।

प्रमुख बिंदु

- भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने गुजरात उच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का उद्घाटन किया।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- मुख्य न्यायाधीश ने "गुजरात उच्च न्यायालय (अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2021" भी जारी किया।

गुजरात उच्च न्यायालय के बारे में:

- यह 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से गुजरात राज्य के विभाजन के बाद बॉम्बे री-ऑर्गनाइजेशन एक्ट, 1960 के तहत स्थापित किया गया था।
- गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश: विक्रम नाथ

स्रोत: TOI

'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय' का नाम 'जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय' किया गया

- लंबे समय तक चलने वाले और बोझिल नामकरण 'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय' को 'जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय' में बदल दिया गया है।
- कानून और न्याय मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा आदेश को अधिसूचित किया गया था।
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर किये हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा गया

चर्चा में क्यों?

- उत्तर पूर्वी रेलवे (NER) द्वारा आखिरकार मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का औपचारिक नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन 16 सितंबर, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2020 को दिए गए NOC के अंतर्गत किया गया था।

नोट: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केन्द्र "रुद्राक्ष" का उद्घाटन किया।

स्रोत: TOI



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए 8 नए रूटों का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात तक हवाई संपर्क को मजबूत करने वाले 8 नए रूटों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- स्पाइसजेट एयरलाइंस इन 8 नए मार्गों पर परिचालन शुरू करेगी- ग्वालियर-मुंबई-ग्वालियर, ग्वालियर-पुणे-ग्वालियर, जबलपुर-सूरत-जबलपुर, और अहमदाबाद-ग्वालियर-अहमदाबाद रूट।
- ग्वालियर मध्य प्रदेश के पहले हवाई अड्डों में से एक है जो उड़ान (UDAN) रूट से जुड़ा है।
- इन मार्गों की शुरुआत से उड़ान योजना के तहत सब उड़ें, सब जुड़ें का लक्ष्य प्राप्त होगा। जिससे देश में स्थापित हवाई नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के बारे में:

- RCS-UDAN भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा प्रदान करना है।
- यह RCS (क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना) आम आदमी को किफायती मूल्य पर उड़ान भरने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
- उड़ान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) का एक प्रमुख घटक है जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत) द्वारा 15 जून 2016 को जारी किया गया था।
- नोट: इस महीने की शुरुआत में, उड़ान योजना के तहत, इंडिगो एयरलाइंस ने कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और इंफाल (मणिपुर) को डिब्रूगढ़ (असम) से जोड़ने के लिए एक और उड़ान शुरू की।
- उड़ान योजना के तहत अब तक 359 मार्ग और 5 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 59 हवाई अड्डों का संचालन किया जा चुका है।

स्रोत: PIB

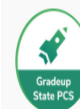
हरियाणा में भारत का पहला 'अनाज ATM'

चर्चा में क्यों?

- हरियाणा सरकार ने हाल ही अपनी पहली ATM मशीन 'अन्नपूर्ति' खाद्यान्न वितरण के लिए में गुरुग्राम के फरुखनगर में स्थापित की है, जो तीन प्रकार के अनाज - गेहूं, चावल और बाजरा प्रदान करेगी।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- यह मशीन संयुक्त राष्ट्र के "विश्व खाद्य कार्यक्रम" के तहत स्थापित है और इसे ऑटोमेटेड, मल्टी कमोडिटी, अनाज वितरण मशीन कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु

- इस ATM का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित राशन की दुकानों पर अनाज के वितरण को आसान और परेशानी मुक्त बनाना है।
- प्रत्येक मशीन एक बार में पांच से सात मिनट के अन्दर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है।
- यह एक स्वचालित मशीन है; इसलिए अनाज की माप में त्रुटि की गुंजाइश नगण्य है।
- मशीन में टच-स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम है, जहां लाभार्थियों को अपना अनाज प्राप्त करने के लिए अपना आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा।

स्रोत: TOI

Important News: India

सरकार ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया चर्चा में क्यों?

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए **केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989** में संशोधन किया है।
- इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

विंटेज मोटर वाहनों के बारे में:

- मसौदा नियम विंटेज मोटर वाहनों को उन सभी वाहनों के रूप में परिभाषित करते हैं जो दोपहिया और चार पहिया वाहन हैं और उनके पहले पंजीकरण (आयातित वाहन सहित) की तारीख से 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- विंटेज मोटर वाहनों को नियमित/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

भारत में जल क्षेत्र के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ने जल क्षेत्र में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से पैदा हुए अवसरों पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन द एसोसिएशन ऑफ जियोस्पेशियल इंडस्ट्रीज ने 'पोटेंशियल ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजिज फॉर द वाटर सेक्टर इन इंडिया' यानी भारत में जल क्षेत्र के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की क्षमता शीर्षक के तहत यह रिपोर्ट तैयार की है।
- जनसंख्या घनत्व और कृषि के लिए पानी की आवश्यकता के मद्देनजर भारत भू-जल पर बहुत अधिक निर्भर है। जहां तक जल संकट का सवाल है तो यह सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- देश में प्रमुख जल क्षेत्र के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम में किस प्रकार फिलहाल भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है और भविष्य में प्रौद्योगिकी को अपनाने में
- रिपोर्ट के अनुसार, जल संकट से निपटने के लिए उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग, सर्वेक्षण एवं मैपिंग, GPS आधारित उपकरण एवं सेंसर, GIS एवं स्पेशियल एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, रोबोटिक्स और डिजिटल ट्विन जैसी भू-स्थानिक एवं डिजिटल तकनीकों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत में जल परियोजनाएं:

- राष्ट्रीय नदी जोड़ने की परियोजना
- जल जीवन मिशन
- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना
- नमामि गंगे मिशन
- राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)
- राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम
- नदी बेसिन प्रबंधन
- राष्ट्रीय जल मिशन
- अटल भूजल योजना

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के बारे में:

- यह एक शब्द है जिसका उपयोग पृथ्वी और मानव समाज के भौगोलिक मानचित्रण और विश्लेषण में योगदान करने वाले आधुनिक उपकरणों की श्रेणी का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- इसे भौगोलिक जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और संग्रहीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



सबसे आम भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां:

- रिमोट सेंसिंग
- जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम्स (GIS)
- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS)
- इंटरनेट मैपिंग टेक्नोलॉजीज

स्रोत: PIB

मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 340** के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 31 जुलाई 2021 से आगे 6 महीने के लिए और 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहने वाले **ग्यारहवें विस्तार** को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

लाभ

- इस "आयोग" के कार्यकाल और इसके संदर्भ की शर्तों में प्रस्तावित विस्तार इसे विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा।

आयोग (रोहिणी आयोग):

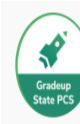
- आयोग 2 अक्टूबर 2017, राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित किया गया था।
- आयोग सेवानिवृत्त दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश श्रीमती जी रोहिणी की अध्यक्षता में है।
- यह सभी OBC समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व का "समान वितरण" सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण के लिए OBC के भीतर श्रेणियां बनाने की संभावना की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था।

नोट:

- वर्तमान में, OBC को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाता है।
- केन्द्रीय सूची में 2,633 अन्य पिछड़ी जातियां हैं और इस साल की शुरुआत में आयोग ने उन्हें चार उपश्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, जिनकी संख्या 1, 2, 3 और 4 थी और 27% को क्रमशः 2, 6, 9 और 10% में विभाजित किया गया था।
- आयोग ने सभी OBC रिकॉर्ड के पूर्ण डिजिटलीकरण और OBC प्रमाण पत्र जारी करने की एक मानकीकृत प्रणाली की भी सिफारिश की थी।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340:

- राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करने के लिये तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान के लिये एक

नोट: सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, 1955 या काका कालेलकर आयोग के रूप में भी जाना जाता है।

स्रोत: PIB

भारतीय श्रम सम्मेलन चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय मजदूर संघ (लेबर यूनियन) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) आयोजित करने का आह्वान किया है।
- भारतीय संसद ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन नंबर 144 की पुष्टि की है, अतः इस त्रिपक्षीय तंत्र को मज़बूत करने हेतु ILC का आयोजन करना भारत सरकार का कानूनी दायित्व है।

प्रमुख बिंदु

भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) के बारे में:

- यह श्रम और रोजगार मंत्रालय में शीर्ष स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समिति है।
- यह देश के मजदूर वर्ग से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सुझाव देता है।
- **सदस्य:** केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन, नियोक्ताओं के केंद्रीय संगठन, सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश और एजेंडा से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, ILC के सदस्य हैं।
- ILC की पहली बैठक (जिसे तब त्रिपक्षीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहा जाता था) 1942 में हुई थी और अब तक कुल 46 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।
- भारतीय श्रम सम्मेलन का सबसे हालिया सत्र 2015 में आयोजित किया गया था।

मजदूर वर्ग के लिए कुछ सरकारी पहल:

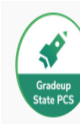
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
- नए श्रम संहिता, 2020
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना
- व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

ILO कन्वेंशन नंबर 144 के बारे में:

- त्रिपक्षीय परामर्श पर कन्वेंशन (अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक), 1976 (नंबर 144), ILO के एक संस्थापक सिद्धांत के अनुप्रयोग को बढ़ावा



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



देता है: अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को विकसित करने, लागू करने और बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद के माध्यम से सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे में:

- यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका जनादेश अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है।

मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड

महानिदेशक: गाइ राइडर

स्थापना: 11 अप्रैल 1919

- ILO में 187 सदस्य राज्य हैं।
- भारत ILO का संस्थापक सदस्य है।

स्रोत: द हिंदू

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज' स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय होगा जो भारत की समृद्ध मूर्त विरासत में संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा।

प्रमुख बिंदु

'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज' के बारे में:

- संस्थान को डीम्ड यनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
- **नोट:** वर्तमान में, भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। भारत में दुनिया की छठी सबसे बड़ी साइट्स हैं। भारत के इन 38 UNESCO धरोहर स्थलों में से इस सूची में 30 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं।
- वर्तमान में, कुल 167 देशों में 1,121 विश्व विरासत स्थल (869 सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक, और 39 मिश्रित) मौजूद हैं। 55 चयनित क्षेत्रों के साथ, चीन और इटली सूची में सबसे अधिक साइट्स वाले देश हैं।

स्रोत: PIB

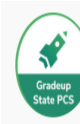
AI- संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लिकेशन

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)- संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- वेब-आधारित एप्लिकेशन को संयुक्त रूप से **रक्षा मंत्रालय, DARPG (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग) और IIT कानपुर** द्वारा विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह परियोजना शिकायत निवारण में AI, डेटा विज्ञान और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करने के लिए सरकार की अपनी तरह की पहली पहल है।
- यह AI-पावर्ड एप्लिकेशन लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से संभालेगा और उनका विश्लेषण करेगा और मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, समय बचाएगा और उनके निपटान में अधिक पारदर्शिता लाएगा।
- यह एक श्रेणी में शिकायतों के भौगोलिक विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है जिसमें यह विश्लेषण भी शामिल है कि शिकायत का संबंधित कार्यालय द्वारा ठीक प्रकार से निपटारा किया गया या नहीं।

नोट:

- हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्टस एफिशिएंसी (SUPACE)** लॉन्च किया। SUPACE, न्यायाधीशों के लिए अनुसंधान को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उनका कार्यभार आसान हो गया है।
- **AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)** का अर्थ है मशीनों में मानव बुद्धि का अनुकरण जो मनुष्यों की तरह सोचने और उनके कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं।

स्रोत: PIB

डिजिटल प्लेटफॉर्म 'किसान सारथी'

चर्चा में क्यों?

- डिजिटल प्लेटफॉर्म 'किसान सारथी' संयुक्त रूप से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।
- इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- डिजिटल प्लेटफॉर्म **किसान सारथी** किसानों को उनकी भाषा में '**सही समय पर सही जानकारी**' प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह डिजिटल प्लेटफॉर्म दूर-दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाएगा।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- यह किसानों को **कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)** के संबंधित वैज्ञानिकों से सीधे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर बातचीत करने और व्यक्तिगत सलाह लेने में मदद करेगा।
- यह ICAR की कृषि विस्तार, शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों में अत्यधिक मूल्यवान होगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के बारे में:

- ICAR कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी।
- ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है।

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK):

- कृषि विज्ञान केंद्र भारत में एक कृषि विस्तार केंद्र है।
- आमतौर पर एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े, ये केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं, और एक व्यावहारिक, स्थानीय व्यवस्था में कृषि अनुसंधान को लागू करने का लक्ष्य रखते हैं।
- मई 2021 तक, पूरे भारत में लगभग 722 KVK थे।
- पहला **कृषि विज्ञान केन्द्र** 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था।

अन्य संबंधित पहलें:

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM)
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड

स्रोत: PIB

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "उमंग ऐप" में मानचित्र सेवाओं को

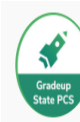
सक्षम बनाया

चर्चा में क्यों?

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने **मैप माई इंडिया** के साथ एक समझौता जापन के माध्यम से **उमंग (UMANG)** (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) मोबाइल ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बनाया।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



प्रमुख बिंदु

- नागरिक एक बटन के क्लिक पर अपने आस पास के निकटतम स्थान पर सरकारी सुविधाएं, जैसे मंडियां, ब्लड बैंक और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- वे इसे मैप माई इंडिया द्वारा निर्मित भारत के सबसे विस्तृत और संवादात्मक सड़क और ग्राम स्तर के नक्शों पर भी देख सकेंगे।
- नागरिक उमंग ऐप और मैप माई इंडिया के बीच संपर्क के माध्यम से नेविगेशन के दौरान यातायात और सड़क सुरक्षा अलर्ट सहित स्थानों के लिए ड्राइविंग दूरी, दिशा-निर्देश और बारी-बारी से ध्वनि और दृश्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उमंग मोबाइल ऐप (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) के बारे में:

- उमंग भारत सरकार का एकल, एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी-चैनल, मल्टी-प्लेटफॉर्म, बहुभाषी, मल्टीसर्विस मोबाइल ऐप है, जो उच्च प्रभाव वाली सेवाओं विभिन्न संगठन (केंद्र और राज्य) तक पहुंच प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में उमंग ऐप की शुरुआत की थी।

नोट: उमंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण 2020 में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय अंतरराष्ट्रीय छात्रों, NRI और विदेशों में भारतीय पर्यटकों को, कभी भी, भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।

मैप माई इंडिया के बारे में:

- मैप माई इंडिया, 1995 में नई दिल्ली, भारत में स्थापित और मुख्यालय वाली एक स्वदेशी कंपनी का उत्पाद है, जिसने पूरे देश का डिजिटल रूप से मानचित्रण किया है।
- यह उपयोगकर्ताओं को आसपास के प्रासंगिक स्थानों को खोजने और उन्हें विस्तृत भवन स्तर के नक्शे पर देखने में मदद करता है।

स्रोत: PIB

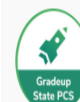
स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने संयुक्त रूप से 'स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम' (स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम) (SIATP) का शुभारम्भ किया।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक आदि-प्रशिक्षण पोर्टल की शुरुआत की है जो प्रशिक्षण सामग्री का भंडार भी है।

प्रमुख बिंदु



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में:

- स्कूली शिक्षकों के लिए यह अभिनव और अपनी तरह का अनूठा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, IPR, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि के बारे में प्रशिक्षण देना है।
- प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा।
- कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष एकांश और AICTE द्वारा स्कूली शिक्षकों के लिए "उच्च शैक्षिक संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए नवाचार राजदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" के आधार पर डिजाइन किया गया है।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष एकांश, जनजातीय कार्य मंत्रालय, CBSE और AICTE द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है।

लाभ:

- 'SIATP' लाखों छात्रों को नवाचार क्षमताओं के साथ पोषित करेगा, नवाचार की संस्कृति विकसित करेगा तथा एक नए और जीवंत भारत की नींव रखेगा।
- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) के छात्रों को स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम से बहुत लाभ होगा क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय का भी प्रयास है कि आदिवासी बच्चों को हरसंभव सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान की जाए।
- आदिवासी बच्चों के लिए EMRS प्रधानमंत्री का एक और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके तहत अगले तीन वर्षों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 740 ऐसे विद्यालय स्थापित किए जाएं।

अन्य महत्वपूर्ण संबंधित पहलें:

- नई शिक्षा नीति, 2020
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फार नालेज शेयरिंग एप (दीक्षा)
- समग्र शिक्षा
- स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (NISHTHA)
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के बारे में: यह एक वैधानिक निकाय है, और उच्च शिक्षा विभाग के तहत तकनीकी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद है।

स्थापना: नवंबर 1945

मुख्यालय: नई दिल्ली

चेयरपर्सन: अनिल सहस्रबुद्धे

स्रोत: PIB



Important News: World

अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान क्वाड समूह का गठन करेंगे

चर्चा में क्यों?

- बाइडेन प्रशासन के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक नया चार सदस्यीय राजनयिक मंच स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- पार्टियां अफगानिस्तान में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता को क्षेत्रीय संपर्क के लिए महत्वपूर्ण मानती हैं और इस बात पर सहमत हैं कि शांति और क्षेत्रीय संपर्क
- पार्टियां का इरादा व्यापार का विस्तार करने, पारगमन लिंक बनाने और व्यापार-से-व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करना है, ताकि अंतर्देशीय व्यापार मार्गों को खोलने के ऐतिहासिक अवसर को पहचाना जा सके।

नोट:

- अफगानिस्तान, जो ऐतिहासिक सिल्क रोड के केंद्र में है, लंबे समय से एशियाई देशों के बीच व्यापार के लिए एक चौराहे के रूप में कार्य करता है, उन्हें यूरोप से जोड़ता है और धार्मिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध स्थापित करता है।
- अफगानिस्तान में अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव (BRI) का विस्तार करने के चीन के इरादे को देखते हुए नए क्वाड समूह की स्थापना महत्वपूर्ण है।
- बेल्ट रोड इनिशिएटिव (BRI) दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिए भूमि और समुद्री कनेक्शन का एक नेटवर्क बनाने का इरादा रखता है।
- अफगानिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण चीन के लिए दुनिया भर में अपना प्रभाव फैलाने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में काम कर सकता है।

स्रोत: इकोनामिक टाइम्स

Important News: Economy

स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ाया गया

चर्चा में क्यों?

- वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ने बताया कि स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रमुख बिंदु



स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में:

- यह योजना 05 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी थी।

उद्देश्य और ऋण की प्रकृति:

- इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम-से-कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम-से-कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सविधा प्रदान करना है।
- यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं, कृषि-संबद्ध गतिविधियों या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है।
- गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
- SIDBI और NABARD के कार्यालय स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर (SUCC) नामित हैं।

नया परिवर्तन:

- FY 2021-22 के लिए, योजना के तहत ऋण के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता '25% तक' से घटाकर '15% तक' कर दी गई है और कृषि से जुड़ी गतिविधियों को योजना में शामिल किया गया है।

प्रदर्शन:

- 28.06.2021 को 26204.49 करोड़ रुपये के कुल 1,16,266 ऋण योजना के तहत शुरुआत से ही बढ़ाए जा चुके हैं।

स्रोत: PIB

भारत दुनिया में 5वें सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में उभरा

चर्चा में क्यों?

- भारत 25 जून, 2021 तक चीन, जापान, स्विटजरलैंड और रूस के बाद में 608.99 अरब डॉलर के साथ दुनिया में 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में उभरा है।
- इसकी सूचना वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा 20 जुलाई, 2021 को लोकसभा में दी गयी थी।

प्रमुख बिंदु

- सरकार और RBI मजबूत समष्टि आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए नीतियों या विनियमों को कैलिब्रेट करने वाली उभरती बाहरी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

- भारतीय रिजर्व बैंक सुरक्षा और तरलता मानकों का पालन करते हुए, विदेशी मुद्रा स्वेप और रेपो बाजारों में परिचालन को बढ़ाकर, सोने के अधिग्रहण और नए बाजारों / उत्पादों की खोज करके विदेशी मुद्रा भंडार के विविधीकरण के लिए नियमित कदम उठाता है।
- **नोट:** 2020-21 में, भारत के भुगतान संतुलन ने चालू खाते और पूंजी खाते दोनों में अधिशेष दर्ज किया, जिसने वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में योगदान दिया।
- **विदेशी मुद्रा भंडार:** विदेशी मुद्रा भंडार नकद और अन्य आरक्षित परिसंपत्तियां हैं जैसे केंद्रीय बैंक या अन्य मौद्रिक प्राधिकरण के पास मौजूद सोना जो मुख्य रूप से देश के भुगतान संतुलन के लिए उपलब्ध हैं।

स्रोत: PIB

Important News: Health

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने राज्यसभा को **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के बारे में जानकारी दी।
- NHM समर्थित स्वास्थ्य प्रणाली में सुधारों के परिणामस्वरूप लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों का विकास हुआ है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के बारे में:

- NHM को भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) (2005 में शुरू किया गया) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) (2013 में शुरू किया गया) को मिलाकर शुरू किया गया था।
- **NHM सहायता** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मानदंडों के अनुसार नई सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर बनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने के लिए प्रदान की जाती है।
- **NHM सहायता** मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, और तपेदिक जैसी प्रमुख बीमारियों, डेंगू, मलेरिया और कुष्ठ रोग जैसे वेक्टर जनित रोगों आदि से संबंधित कई मुफ्त सेवाओं के प्रावधान के लिए भी प्रदान की जाती है।

NHM के तहत समर्थित अन्य प्रमुख पहल:

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
- निःशुल्क दवाओं का क्रियान्वयन और निःशुल्क निदान सेवा पहल
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे का कार्यान्वयन (सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में)
- मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेली-परामर्श सेवाएं (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए लागू)
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- आयुष्मान भारत

NHM की उपलब्धियां

- कार्यान्वयन के 15 वर्षों में, NHM ने स्वास्थ्य के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDG) की उपलब्धि को सक्षम किया है।
- इससे मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य संकेतकों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- **समान विकास:** आदिवासी आबादी, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में रहने वालों और शहरी गरीबों के स्वास्थ्य पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि:** NHM स्वास्थ्य प्रणाली के दृष्टिकोण को अपनाता है और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखता है।
- **राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं**
- **मानव संसाधन वृद्धि:** NHM डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे सेवा वितरण HR को शामिल करने के लिए राज्यों का समर्थन करता है और आशा (ASHA) के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम को भी लागू करता है।
- **उच्च आउट-ऑफ-पैकेट व्यय (OOPE):** OOPE के वर्तमान उच्च स्तर को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि OOPE का लगभग 70% हिस्सा दवाओं और निदान के कारण है, NHM के तहत मुफ्त दवाएँ और निःशुल्क नैदानिक सेवा संबंधी पहल लागू की गई है।

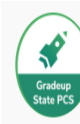
स्रोत: PIB

पंजाब SOHUM (AABR) शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना
चर्चा में क्यों?

- पंजाब सरकार ने यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत SOHUM-ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पांस सिस्टम (AABR) की शुरुआत की।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने सोहम (AABR) की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- यह पहल नवजात और छोटे बच्चों में श्रवण हानि की प्रभावी रूप से जांच करेगी।
- यह उपकरण निश्चित रूप से प्रभावी मूल्यांकन और समय पर ढंग से श्रवण हानि के प्रबंधन में मदद करेगा।

नोट:

- भारत जैसे विकासशील देश में प्रति हजार 5-6 बच्चे इस दोष के साथ पैदा होते हैं।
- भारत में लगभग 63 मिलियन लोग श्रवण दोष और संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं।

SOHUM के बारे में:

- यह स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायोडिजाइन स्टार्ट-अप SOHUM इनोवेशन लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एक स्वदेशी रूप से विकसित नवजात श्रवण स्क्रीनिंग डिवाइस है।
- इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विकसित किया गया था।

स्रोत: TOI

मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थियों के बच्चों की वृद्धि हुई बेहतर: अध्ययन चर्चा में क्यों?

- एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत में लाभार्थियों के स्कूली बच्चे राष्ट्रीय स्कूल भोजन कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं।
- अध्ययन, जिसे हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, का शीर्षक 'इंटरनेशनल न्यूट्रिशन बेनिफिट्स ऑफ इंडियाज नेशनल स्कूल फीडिंग प्रोग्राम' है।
- इसका वाशिंगटन विश्वविद्यालय के सुमन चक्रवर्ती और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के सैमुअल स्कॉट, हेरोल्ड एल्डरमैन, पूर्णिमा मेनन और डैनियल गिलिगन द्वारा सह-लेखन किया है।

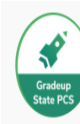
प्रमुख बिंदु

अध्ययन के निष्कर्ष:

- अध्ययन ने 1993 से 2016 तक माताओं और उनके बच्चों पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि डेटा का इस्तेमाल किया ताकि यह आकलन किया जा सके कि मध्याह्न भोजन बच्चे के रैखिक विकास में अंतर-पीढ़ीगत सुधार का समर्थन करता है या नहीं।
- प्राथमिक विद्यालय में मुफ्त भोजन प्राप्त करने वाली महिलाओं में बेहतर रैखिक विकास वाले बच्चे होते हैं।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

[Subscribe Now](#)



- अध्ययन में पाया गया कि 1990 के दशक के अंत में जिन 14 राज्यों ने मध्याह्न भोजन की शुरुआत की, उनमें देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बच्चों की लंबाई में सुधार हुआ।
- स्कूली भोजन शिक्षा, बाद में प्रजनन संबंधी निर्णयों और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में योगदान दे सकता है, जिससे अगली पीढ़ी में अल्पपोषण के जोखिम को कम किया जा सकता है।

मध्याह्न भोजन योजना के बारे में:

- मध्याह्न भोजन योजना 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी ताकि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा I-V; आयु 6-10 वर्ष) में बच्चों को मुफ्त पका भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
- बाद में, इस योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बढ़ा दिया गया था।
- मध्याह्न भोजन योजना भारत में एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है जिसे देश भर में स्कूली उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति योजना के कार्यान्वयन को देखरेख करती है।
- मध्याह्न भोजन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आती है।
- तमिलनाडु इस योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य था।

वैश्विक भूख सूचकांक 2020:

- वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है और 'गंभीर' भूख श्रेणी में है।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020:

- भारत उन 88 देशों में शामिल है जिनके 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों से चूकने की संभावना है।

स्रोत: द हिंदू

Important News: Defense

DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश-NG का सफल परीक्षण किया

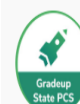
चर्चा में क्यों?

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के तट के करीब एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी आकाश मिसाइल (आकाश-NG) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL), हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है।
- परीक्षण के दौरान, मिसाइल ने तेज और फुर्तीले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए आवश्यक उच्चस्तरीय गतिशीलता का प्रदर्शन किया।

स्रोत: PIB

तीन देशों का टेबल टॉप नौसैनिक अभ्यास 'शील्ड'

चर्चा में क्यों?

- श्रीलंकाई नौसेना, मालदीव के नेशनल डिफेंस फ़ोर्स तथा भारतीय नौसेना के बीच एक तीन देशों का टेबल टॉप एंटी नारकोटिक्स एंड मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू अभ्यास (एक्सरसाइज शील्ड) मुंबई में WNC में पहली बार दिनांक 14 और 15 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना की अगुवाई में आभासी रूप से आयोजित किया गया था।
- इस अभ्यास का समन्वय मेरीटाइम वारफेयर सेंटर, मुंबई द्वारा किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- एंटी-नारकोटिक ऑपरेशंस और मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर प्रतिभागियों द्वारा विचार-विमर्श किया गया, जिनकी हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख शिपिंग मार्गों पर एक विशेष भौगोलिक स्थिति है।
- यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे आम अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं/प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान, सूचना/खुफिया सूचना के आदान-प्रदान के तौर-तरीकों को विकसित करने और समुद्री खोजबीन और बचाव में एक दूसरे की सहायता करने पर केंद्रित था।

नोट:

- अप्रैल में, नौसेना ने अरब सागर में मछली पकड़ने के एक जहाज से 300 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ बरामद किए थे, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,000 करोड़ रुपये थी।
- नौसेना ने तब कहा था कि यह तस्करी मार्गों को बाधित करने के मामले में एक बड़ी पकड़ थी, जो मकरान तट से निकलती है और भारतीय, मालदीव और श्रीलंकाई गंतव्यों की ओर बहती है।

स्रोत: द हिंदू

Environment



दो भारतीय संगठनों ने UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2021 जीता

चर्चा में क्यों?

- जैव विविधता हानि और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थानीय, अभिनव, प्रकृति-आधारित समाधानों को प्रदर्शित करने में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए दो भारतीय संगठनों ने प्रतिष्ठित UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2021 प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

- विश्व स्तर पर दस विजेताओं में से भारत की ओर से दो संगठन हैं- अधिमलाई पझंगुडियिनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेहकुंजा ट्रस्ट।
- उनमें से प्रत्येक को 10,000 अमरीकी डालर का पुरस्कार और इस वर्ष के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा, द नेचर फॉर लाइफ हब और UN फूड सिस्टम्स समिट से जुड़े विशेष आभासी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

अधिमलाई पझंगुडियिनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बारे में:

- दक्षिण भारत में नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व के स्वदेशी लोगों द्वारा प्रबंधित और पूरी तरह से संचालित इस 1,700 सदस्यीय सहकारी ने वन उत्पादों और फसलों की विविध श्रेणी के प्रसंस्करण और विपणन द्वारा 147 गांवों में आजीविका में सुधार किया है।

स्नेहकुंजा ट्रस्ट के बारे में:

- स्नेहकुंजा ट्रस्ट ने 45 वर्षों के लिए पश्चिमी घाट और कर्नाटक तट में संवेदनशील आर्द्रभूमि और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की है। स्नेहकुंजा ट्रस्ट भारत में वर्तमान में पहली ब्लू कार्बन परियोजना का संचालन कर रहा है।

इक्वेटर पुरस्कार के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत इक्वेटर इनिशिएटिव द्वारा आयोजित इक्वेटर पुरस्कार, जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए उत्कृष्ट सामुदायिक प्रयासों को मान्यता देने के लिए द्विवार्षिक रूप से

प्रदान किया जाता है।
स्रोत: undp.org

Awards and Honours

भारत सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की
चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की दो श्रेणियां हैं, पहले में लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर/ सेवा प्रदाता शामिल हैं और दूसरी विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए है।
- पुरस्कारों से लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल विभिन्न कंपनियों को पहचान मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

पुरस्कारों के बारे में:

- इन पुरस्कारों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जिन्होंने अन्य उपलब्धियों के साथ ही परिचालन उत्कृष्टता हासिल की है, डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को अपनाया है, ग्राहक सेवा में सुधार किया है और विकास परिणामों में योगदान दिया है।
- उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए, ये पुरस्कार आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव, आपूर्ति व्यवस्था का विकास, कौशल विकास, स्वचालन और अन्य ऐसे कार्यों की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रदर्शन किया जाएगा।

नोट:

- भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र जहां 2020 में लगभग 215 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के साथ 10.5 प्रतिशत CAGR दर से बढ़ रहा है, वहीं इसके साथ ही व्यवस्थित, एक दूसरे से जुड़ी समस्याएं हैं जिन्हें उसकी दक्षता में सुधार के लिए दूर किया जाना चाहिए।
- भारत के GDP में लॉजिस्टिक की समग्र लागत लगभग 14 प्रतिशत आती है। 8 प्रतिशत के वैश्विक औसत की तुलना में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता के अंतर को कम करने के लिए भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र को वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में शीर्ष 25 देशों में शामिल होने की महत्वाकांक्षा के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तरह उन्नत, संगठित और कुशल बनाना होगा।

स्रोत: PIB

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2021

- 74वां कान्स फिल्म फेस्टिवल कान्स, फ्रांस में आयोजित किया गया।
- अमेरिकी निर्देशक और पटकथा लेखक स्पाइक ली कान्स फिल्म फेस्टिवल 2021 के जूरी अध्यक्ष थे।

मुख्य विजेताओं की सूची:

- पाल्मे डी'ओर: "टाइटेन" (फ्रांस) के लिए जूलिया डुकोर्नो
- ग्रांड प्रिक्स: "ए हीरो" (ईरान) के लिए अशगर फरहादी और "कम्पार्टमेंट नंबर 6" (फिनलैंड) के लिए जुहो कुओसमैनन



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: "एनेट" (फ्रांस) के लिए लेओस कैरैक्स
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: "नाइट्राम" (US) के लिए कालेब लैंड्री जोन्स
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: "वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड" (नॉर्वे) के लिए रीनेट रीन्सवे
- जूरी पुरस्कार: "अहेड्स नी" (इज़राइल) के लिए नदव लैपिड और "मेमोरिया" (थाईलैंड) के लिए एपिचटपोंग वीरासेथकुल
- सर्वश्रेष्ठ पटकथा: "ड्राइव माई कार" (जापान) के लिए हमागुची रयूसुके और ताकामासा ओए

नोट: मुंबई की फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए L'Oeil d'Or: Le Prix du documentaire, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार जीता।

कान्स फिल्म फेस्टिवल के बारे में:

- कान्स फिल्म फेस्टिवल कान्स, फ्रांस में आयोजित एक वार्षिक फिल्म समारोह है जो दुनिया भर से वृत्तचित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों का पूर्वावलोकन करता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी।
- दो प्रमुख पुरस्कार पाल्मे डी'ओर और ग्रैंड प्रिक्स हैं।

स्रोत: TOI

Reports

स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट (विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021)

चर्चा में क्यों?

- स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट 2020 के लिए खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का पहला वैश्विक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है और इस बात का कुछ संकेत देती है कि 2030 तक भूख की स्थिति कैसी हो सकती है, एक ऐसे परिदृश्य में जो COVID-19 महामारी के स्थायी प्रभावों से और अधिक जटिल है।
- रिपोर्ट FAO (खाद्य और कृषि संगठन), IFAD (कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष), UNICEF, WFP (विश्व खाद्य कार्यक्रम) और WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एक वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है।

प्रमुख बिंदु



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- यह सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के संदर्भ में भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और पोषण में सुधार लाने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख चुनौतियों पर गहन विश्लेषण प्रदान करने की दिशा में प्रगति की सूचना देती हैं।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- जनसंख्या के संदर्भ में, यह अनुमान लगाया गया है कि 2020 में दुनिया में 720 और 811 मिलियन लोगों के बीच भूख का सामना करना पड़ा। अनुमानित सीमा (768 मिलियन) के मध्य को ध्यान में रखते हुए, 2019 की तुलना में 2020 में 118 मिलियन अधिक लोग भूख का सामना कर रहे थे, अनुमान के साथ 70 से 161 मिलियन तक।
- 2020 में कुपोषित लोगों की कुल संख्या (768 मिलियन) में से आधे से अधिक (418 मिलियन) एशिया में और एक तिहाई (282 मिलियन) से अधिक अफ्रीका में रहते हैं, जबकि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में लगभग 8 प्रतिशत (60 मिलियन) हैं।
- 2014 से 2019 तक लगभग अपरिवर्तित रहने के बाद, 2019 और 2020 के बीच अल्पपोषण (PoU) की व्यापकता 8.4 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 9.9 प्रतिशत हो गई, जिससे 2030 में शून्य भूख लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौती बढ़ गई।
- वैश्विक स्तर पर मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा (खाद्य असुरक्षा अनुभव पैमाने के आधार पर) धीरे-धीरे बढ़ रही है, 2014 में 22.6 प्रतिशत से 2019 में 26.6 प्रतिशत हो गई है। फिर 2020 में, जिस वर्ष COVID-19 महामारी फैल गई, वह पूरे विश्व में फैल गई। ग्लोब, यह पिछले पांच वर्षों में संयुक्त रूप से लगभग बढ़कर 30.4 प्रतिशत हो गया।
- इस प्रकार, दुनिया में लगभग तीन में से एक व्यक्ति के पास 2020 में पर्याप्त भोजन नहीं था - केवल एक वर्ष में 320 मिलियन लोगों की वृद्धि, 2.05 से 2.37 बिलियन तक।

भारतीय परिदृश्य

कुपोषण की स्थिति:

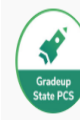
- 2018-20 के दौरान भारत में कुल आबादी के बीच कुपोषण का प्रसार 15.3% था।
- देश में वयस्क आबादी में मोटापे की व्यापकता 2012 में 3% से बढ़कर 2016 में 3.9% हो गई है।
- प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया का प्रसार 2012 में 53.2% से 2019 में 53% तक मामूली सुधार हुआ है।

संबंधित पहल:

- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना
 - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- www.fao.org

Important Days

18 जुलाई, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस

चर्चा में क्यों?

- नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेल्सन मंडेला के सम्मान में एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मंडेला के जन्मदिन पर मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- 2021 का विषय "वन हैंड कैन फीड अदर" है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) ने आधिकारिक तौर पर 2009 में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। यह पहली बार 2010 में मनाया गया था।

नेल्सन मंडेला के बारे में:

- नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे।
- उन्हें व्यापक रूप से सामाजिक न्याय के नेता और लोकतंत्र के कट्टर समर्थक के रूप में माना जाता है।
- उन्हें 250 से अधिक सम्मान मिले और उन्हें 1993 में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

स्रोत: TOI

17 जुलाई, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस

चर्चा में क्यों?

- विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती प्रणाली को पहचानने के प्रयास के रूप में मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।

प्रमुख बिंदु

- 2021 का विषय "ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकॉनमी" है।
- 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बनाने वाली संधि को अपनाने की तारीख है।
- 1 जून 2010 को, कंपाला (युगांडा) में आयोजित रोम संविधि की समीक्षा सम्मेलन में, राज्य दलों की सभा ने 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

[Subscribe Now](#)



स्रोत: TOI

Obituaries

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन

- सुरेखा सीकरी ने थिएटर, फिल्मों और टेलीविजन में काम किया।
- उन्हें तमस (1988), मम्मो (1995) और बधाई हो (2018) सहित तीन बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।
- उन्होंने 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन

- पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में अफगान सशस्त्र बलों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर करते समय मारे गए थे।
- वह मुंबई स्थित एक भारतीय फोटो-पत्रकार थे, जो राष्ट्रीय रॉयटर्स मल्टीमीडिया टीम के प्रमुख थे।
- रोहिंग्या शरणार्थी संकट का दस्तावेजीकरण करने के लिए उन्हें 2018 में रॉयटर्स टीम के हिस्से के रूप में पुलित्जर पुरस्कार मिला।

स्रोत: द हिंदू

